प्रसार भारती

भारतीय प्रसारण निगम

आकाशवाणी केन्द्र शिमला

07.02.2026 / प्रादेशिक समाचार / 15:00 बजे

मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2025–26 के लिए आर.आई.डी. एफ के तहत 7 सौ 58 करोड़ 81 लाख रुपये का बजट प्रावधान किया है। वित्त वर्ष 2026–27 के लिए विधायकों की प्राथमिकताओं को निर्धारित करने के लिए शिमला में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री ने विभागों से कहा कि आर.आई.डी.एफ. के तहत विधायकों की कोई डी.पी.आर. जिसे नाबार्ड को स्वीकृति के लिए प्रेषित की जा चुकी है और यदि वह डीपीआर किसी अन्य मद से स्वीकृत हो चुकी है तो ऐसी स्थिति में सम्बन्धित विभाग उस डीपीआर को नाबार्ड से वापिस करने के लिए योजना विभाग को शीघ्र लिखें। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य में सुधार राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता है और आने वाले दो वर्षों में 3 हजार करोड़ रुपये हाई–एंड टेक्नोलॉजी पर खर्च किए जाएंगे।

केंद्रीय बजट

केंद्रीय बजट में हिमाचल प्रदेश को राजस्व घाटा अनुदान का प्रावधान खत्म किए जाने पर प्रदेश सरकार की ओर से विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का प्रस्ताव लोकभवन भेजा गया है। जानकारी के अनुसार राज्यपाल ने इसे अभी तक मंजूरी नहीं दी है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे शिमला जिला संवाददाता–––

डिस्पैच : ***विशेष सत्र के बजाय बजट सत्र बुलाने का सरकार को सुझाव दिया है जिसमें आर.जी.डी. के मुद्दे पर भी चर्चा की जा सकती है। इस बीच विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया खुद शुक्रवार लोकभवन पहुंचे और विशेष सत्र के प्रस्ताव पर मंजूरी देने के लिए राज्यपाल से चर्चा की लेकिन राज्यपाल की ओर से बजट सत्र बुलाने का सुझाव दिया गया है। विपक्ष ने भी विशेष सत्र बुलाने के बजाय बजट सत्र के दौरान इस मुद्दे पर चर्चा किए जाने की बात कही है। ऐसे में अब सत्र को मंजूरी न मिलने से सरकार और लोकभवन के बीच खिंचाव बढ़ने के आसार हैं। वहीं आर. डी.जी. खत्म किए जाने पर सरकार ने कल रविवार को मंत्रिमंडल और सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है जिसमें इस मुद्दे पर चर्चा होगी। सरकार आर.जी.डी के मुद्दे पर विपक्ष का भी सहयोग मांग रही ताकि केंद्र सरकार पर बहाली के लिए दबाव बनाया जा सके। ' ' 52''***

सुरेश कश्यप

सांसद सुरेश कश्यप ने केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट को विकसित भारत की दिशा में ऐतिहासिक करार दिया है। नाहन में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार के फैसलों का लोगों को सीधा लाभ मिल सके। इस बात का बजट में विशेष ध्यान रखा गया है। सुरेश कश्यप ने कहा कि बजट में मुख्य रूप से आर्थिक विकास, औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन सहित आम लोगों की उम्मीदों का भी विशेष रूप से ध्यान रखा गया है।

विनय कुमार

सिरमौर जिले में रेणुकाजी विधानसभा क्षेत्र में बनने वाली रेणुका बांध परियोजना की टेंडर प्रकिया शुरू हो गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने इस प्रक्रिया को क्षेत्र के विकास की दिशा में एक बड़ा कदम

बताया है। उन्होंने कहा कि बांध से प्रभावित परिवारों की सूची में अब एक सौ 50 भूमिहीन और आवासहीन लोगों को भी शामिल किया गया है, जिससे इन परिवारों को भी राहत और न्याय मिल सकेगा।

विनय कुमार ने कह कि कांग्रेस पार्टी और सरकार प्रदेश के विकास के लिए काम कर रही है और आने वाले समय में कई बड़े फैसले जनता के हित में लिए जाएंगे।

पी.एम.ए.वाई–जी–आवास

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के अंतर्गत केन्द्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को तीन करोड़ 87 लाख से अधिक आवास की मंजूरी दी है। ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉ. चंद्र शेखर पेम्मासानी ने राज्यसभा में बताया कि इस वर्ष 2 फरवरी तक दो करोड़ 95 लाख से अधिक घरों का निर्माण पूरा हो चुका है। उन्होंने बताया कि पिछले पांच वर्ष में दो करोड़ 10 लाख 66 हजार से अधिक मकानों की मंजूरी दी गई है। ग्रामीण विकास मंत्रालय पहली अप्रैल, 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण का कार्यान्वयन कर रहा है, जिसका लक्ष्य मार्च 2029 तक चार करोड़ 95 लाख मकानों का निर्माण करना है।

चैंपियनशिप

धर्मशाला स्थित केन्द्रीय विश्वविद्यालय को छठी बार आल इंडिया इंटर जोनल वुमन कबडडी चैंपियनशिप की मेजबानी करने का मौका मिला है। इस प्रतियोगिता का आयोजन धर्मशाला में 9 से 12 फरवरी तक किया जाएगा, जिसमें देश भर के विभिन्न विश्वविद्यालयों के 2 सौ से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे। केंन्द्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफैसर सत प्रकाश बंसल ने एक पत्रकार वार्ता में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल 9 फरवरी को उदघाटन समारोह में शिरकत करेंगे।

——